

Result Mitra Daily Magazine

RBI के FCA में वृद्धि और मुद्रा भंडार के घटक

हालिया रिपोर्ट :-

- RBI के अनुसार, उच्च मुद्रास्फीति के बीच USA एवं अन्य विकसित देशों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि के कारण भारत की विदेशी परिसंपत्तियों पर रिटर्न आय का अर्जित ब्याज वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बढ़कर 4.21 % हो गया।



अर्जित ब्याज:-

- विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में बहु-मुद्रा परिसंपत्तियाँ शामिल,
- इनका समावेशन बहु-संपत्ति पोर्टफोलियो के अंतर्गत,
- 31 मार्च 2024 तक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों यानि FCA में प्रतिभूतियों का कुल मूल्य 468.98 बिलियन डॉलर,
- 4.21 % की दर से 19 बिलियन डॉलर से ज्यादा का ब्याज अर्जन,

पिछले 5 वित्तीय वर्ष में FCA पर रिटर्न (%)

- 2019-20 - 2.65
- 2020-21 - 2.10
- 2021-22 - 2.11
- 2022-23 - 3.73
- 2023-24 - 4.21

EFFR

- US फेडरल रिजर्व बैंक ने पिछले 2 वर्षों में प्रभावी संघीय निधि दर यानि (EFFR) को बढ़ाकर 5.33 % कर दिया है, जो दीर्घावधि औसतन 4.61% से ज्यादा है।
- EFFR बैंकों द्वारा एक-दूसरे से धन उधार लेने का निर्धारित ब्याज दर है, जिसका निर्धारण फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (FOMC) द्वारा किया जाता है।
- EFFR के लिए ऊपरी और निचली सीमा का निर्धारण US फेडरल रिजर्व द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य EFFR को लक्ष्य सीमा (5.25 - 5.50) के भीतर समायोजित करना है।
- RBI की मुख्य नीति दर (रेपो रेट) के USA फेडरल रिजर्व बैंक के समकक्ष नीति का दर 5.20 % की सीमा में है, जबकि रेपो रेट 6.50 % है।

USA में मुद्रास्फीति :-

- जून 2024 में समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिये USA में मुद्रास्फीति 3% पर था, जो पिछले वित्तीय वर्ष की मुद्रास्फीति दर 3.3 % से कम है।
- USA में मुद्रास्फीति की दीर्घावधि दर 3.28 % रहा है।
- मुद्रास्फीति के समायोजन के बाद FCA पर अर्जित स्थान RBI के लिये सकारात्मक रहा है।



नोट:- मुद्रास्फीति की दर कम होने या मुद्रास्फीति की स्थिति में उधार देने वाला यानि Creditors (लेनदार) को ज्यादा फायदा होता है, जबकि मुद्रास्फीति की दर ज्यादा होने पर Debtors (देनदार) यानि उधार लेने वालों को ज्यादा लाभ होता है।

सेफ कस्टडी गोल्ड :-

- RBI ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान Bank of England और Bank for international settlements यानि BIS के पास सेफ कस्टडी में रखे हुए सोने को लगभग 50 टन घटाकर 387.26 मीट्रिक टन कर दिया।
- RBI ने उच्च लागत के कारण विदेशों में रखे जाने वाले स्वर्ण भंडार में कमी लाने का निर्णय लिया है।
- इस संदर्भ में RBI ने सूचना के अधिकार के तहत मांगे गए जानकारियों को देने से यह करते हुए मना कर दिया कि मांगी गई सूचना एक्ट की धारा 8(1XA) के तहत छूट प्राप्त श्रेणी में हैं।

RBI का स्वर्ण भंडार :-

- मार्च, 2024 तक RBI के पास 822.10 मीट्रिक टन स्वर्ण था, जिसमें से 408.31 मीट्रिक टन RBI द्वारा स्वयं रखा गया था।



- 387.26 मीट्रिक टन सोना Bank of England के पास गया था, जबकि 26.53 मीट्रिक टन सोना BIS के पास जमा था।
- केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परियोजनाओं के लिये RBI के बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार के प्रयोग करने की वकालत की थी, क्योंकि यह अपेक्षाकृत सस्ता वित्तपोषण होगा।
- RBI के पास इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा जारी किये गये फंड में 5 बिलियन डॉलर तक निवेश करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन 2024 के मार्च तक सिर्फ 932 मिलियन डॉलर का निवेश किया गया था।

RBI के FCA का बंटवारा :-

- मार्च 2024 तक कुल FCA - 570.95 बिलियन डॉलर
- प्रतिभूतियों में निवेश - 468.99 बिलियन डॉलर
- 62.17 बिलियन डॉलर अन्य बैंकों (अन्य देश के केन्द्रीय बैंक) एवं BIS के पास जमा,
- 39.75 बिलियन डॉलर विदेशी वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा।

FCA

- एक बहुमुद्रा पोर्टफोलियो है, जिसमें US डॉलर, यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग एवं जापानी येन जैसी प्रमुख विदेशी मुद्राएं शामिल रहती हैं।



- इसका मूल्य अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है।
- इसका मूल्यांकन स्वयं की मुद्रा के अलावा किसी अन्य विदेशी मुद्रा के आधार पर किया जाता है।
- FCA, RBI के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है।

विदेशी मुद्रा भंडार :

- इसका नियमन RBI द्वारा किया जाता है।
- इसमें बॉण्ड, ट्रेजरी बिल या अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल होता है।
- ज्यादातर विदेशी मुद्रा भंडार US डॉलर में ही आरक्षित किया जाता है।
- भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार के घटक निम्न हैं :-
- विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ यानि FCA

- स्वर्ण भंडार
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानि IMF के पास रिजर्व ट्रेंच
- विशेष आहरण अधिकार (SDR)

रिजर्व ट्रेंच :-

- यह वास्तव में आपातकालीन कोष (Fund) होता है, जिसे IMF के सदस्य देश द्वारा किसी भी समय बिना किसी शर्त के या बिना किसी सेवा शुल्क का भुगतान किए प्राप्त किया जा सकता है।
- यह IMF के प्रत्येक सदस्य देश द्वारा IMF के पास रखा जाता है, जिसका प्रयोग सदस्य देश द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।

SDR

- यह कोई मुद्रा नहीं है, बल्कि एक आरक्षित परिसंपत्ति है।
- इसकी शुरुआत IMF द्वारा 1969 में तब की गई, जब मुद्राएँ सोने की कीमत से जुड़ी हुई थीं और US डॉलर मुख्य अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति होता था।
- SDR की गणना “बास्केट ऑफ करेंसी” में शामिल विभिन्न मुद्रा के औसत भार के आधार पर किया जाता है।
- SDR बास्केट में 5 मुद्राएँ - US डॉलर, यूरो, जापानी येन, रेन्मिन्बी (चीन) एवं पाउंड स्टर्लिंग शामिल हैं।
- निजी व्यक्ति एवं निजी संस्थाएँ धारण नहीं कर सकती हैं।
- IMF प्रत्येक 5 वर्ष या जरूरत पडने पर पहले भी, SDR- बास्केट में शामिल करेंसियों की समीक्षा करता है।

BIS

- 1930 में स्थापना,
- बेसल (स्विट्जरलैंड) में
- BIS का स्वामित्व 63 देशों के केन्द्रीय बैंकों के पास,
- 63 देशों द्वारा दुनिया भर के अन्य देशों का प्रतिनिधित्व,

गोल्ड रिजर्व

- 1991 में पहली बार “भुगतान संतुलन” के संकट को दूर करने के लिये तत्कालीन चंद्रशेखर सरकार द्वारा गोल्ड रिजर्व को गिरवी रखा गया था।

- भारत द्वारा 46.91 टन गोल्ड को Bank of England और Bank of Japan के पास गिरवी रखा गया था, जिसके बाद 400 मिलियन डॉलर का कर्ज भारत को प्राप्त हुआ था।
- कर्ज तो नवंबर 1991 तक ही चुका दिया गया, लेकिन लॉजिस्टिक कारणों से गोल्ड को RBI ने इंग्लैंड में ही रहने दिया।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान RBI ने इंग्लैंड से 100 मीट्रिक टन गोल्ड वापस मंगवाया, क्योंकि RBI को इसके रख-रखाव के लिये Bank of England को भारी रकम चुकाना पड़ता था।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट :-



- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 के अंत तक वैश्विक स्तर पर कुल खनन किये गये सोने का 17% भाग विभिन्न देशों के केन्द्रीय बैंकों के पास जमा है।
- यह मात्रा 36700 मीट्रिक टन के बराबर है।